अध्यक्षीय भाषण

का० ई. बालानंदन

प्रिय साथियों,

सबसे पहले मैं हम सभी की ओर से दक्षिण अफ्रिकी कम्युनिस्ट पार्टी के महा सचिव का. क्रिस हानि की कायरतापूर्ण हत्या पर गहरा दुख एवं संवेदना प्रकट करना चाहूँगा। दक्षिण अफ्रिका में रंगभेद वाली सरकार को स्थिरता प्रदान करने वाले दक्षिण पंथी नस्लवादियों द्वारा 10 अप्रैल को जोहान्स वर्ग में यह हत्या की गई। हत्या की खबर सुनकर सारा विश्व स्तब्ध हो गया। दक्षिण अफ्रिका में रंगभेद के विरुद्ध चलाई जा रही लड़ाई के महान नेतृत्वकर्ता पर हुए कायरता पूर्ण हमले की चारों ओर से भर्त्सना हुई है। का. हानि ने अपनी योग्यता रंगभेद के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व करके दिखाई। उन्होंने समस्या का हल ढूंढने के लिए सभी रंगभेद विरोधी संघर्ष कर्ताओं को शांति पूर्ण समझौता वार्ताओं के लिए सक्रिय करने के भी प्रयास किए। उनके द्वारा अदा की गई इस प्रशंसनीय भूमिका ने ही उन्हें लोगों के दुश्मनों द्वारा किए हमले का निशाना बनाया। उनकी कमी आसानी से पूरी नहीं की जा सकती।

दक्षिण अफ्रिकी लोगों ने एक अन्य जाने माने नेता ओलिवर ताम्बो को खो दिया है। उनका निधन लम्बी बीमारी के बाद 24 अप्रैल को हुआ। वह दक्षिण अफ्रिका के रंगभेद विरोधी आन्दोलन के पिता स्वरूप माने जाते थे। मैं आप सभी की ओर से इन नेताओं के प्रति श्रद्धा प्रकट करता हूँ और ए.एन.सी., एस.ए.सी.पी. तथा सी.ओ.एस.ए.टी.यू. के साथ हम सभी की सुदृढ़ता व्यक्त करता हूँ।

साथियो, मैं कम्युनिस्ट पार्टी आफ नेपाल (यू.एम.एल.) के महा सचिव का. मदन भंडारी की असामयिक मौत पर हम सभी की ओर से दुख प्रकट करता हूँ। और मुझे पार्टी की अस्थायी समिति के सदस्य का. जीवराज आश्रित की जीप की हुई रहस्य-मय दुर्घटना पर भी दुख है। ये कामरेड पार्टी तथा नेपाल के लोगों का नेतृत्व कर रहे थे और उनका आन्दोलन नई उँचाइयों की ओर विकास शील था। इस दुर्भाग्य पूर्ण घटना ने नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (यू एम.एल.) नेपाल के लोगों तथा अन्तर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक आन्दोलन को बुरी तरह से पीछे धकेल दिया है। हम सी.पी.एन. (यू.एम.एल.) के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं।

बंगलौर जनरल काउंसिल के बाद कई महत्वपूर्ण हस्तियाँ गुजर चुकी हैं जिनकी याद हम लोगों के दिमाग में बनी रहेगी। 8 मई को कलकत्ता में विशिष्ट मार्क्सवादी दार्शनिक श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का स्वर्गवास हो गया। 12 मई को श्रेष्ठ कवि श्री शमशेर बहादुर चल बसे। 8 मार्च को लोक लहर के संपादक का. सोहन सिंह की अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण मृत्यु हो गयी। मैं आप सभी की ओर से इन सभी स्वर्गवासी विशिष्ट व्यक्तित्वों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। इस समय के दौरान हमारे कई योग्य कामरेड भी स्वर्गवासी हो गए। मैं उनकी याद में हम सभी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

प्रिय साथियो,

हमारी कामकाजी समिति की यह बैठक ऑरगेनाइजेशनल रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के लिए आयोजित की गई है। यह रिपोर्ट 19-21 फरवरी 1993 को बंगलोर जनरल काउंसिल में हुई हमारी बहस के आधार पर तैयार की गई है। इस रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के लिए हमें अपना समय देना होगा जिसमें हमारे संगठन के विकास की निर्णायक विधि भी होगी। बंगलोर जनरल काउंसिल के बाद हुई कुछ महत्वपूर्ण प्रगतियों पर आपका ध्यान दिलाते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करूँगा।

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संकट

मैंने अपने बंगलोर भाषण में विकसित पूंजीवादी विश्व में आर्थिक संकट के बारे में उल्लेख किया था। इन तीन महीनों के दौरान यहाँ सुधार होने का कोई संकेत दिखाई नहीं देता परन्तु इसके विपरीत स्थिति और खराब हुई है। ताजा आंकड़ों अनुसार बेरोजगारी की दर वृद्धि में हैं वहीं औद्योगिक उत्पादन और जी.डी.पी. की अधिकांश स्थितियों में ह्रास की प्रवृति दिखा रहे हैं।

सभी स्थितियों में आंकड़े बेरोजगारी की वृद्धि दिखाते हैं। बहुसंख्य देशों में औद्योगिक उत्पादन में कमी आने के साथ कुछ स्थितियों में थोड़ी-बहुत वृद्धि भी हुई है। जी.डी.पी. से संबंधित स्थिति भी इसी प्रकार है।

ब्रिटेन में बेरोजगारों की संख्या तीन मिलियन है और बेरोजगारी की दर 11 प्रतिशत है। यूरोपीय समुदाय के देशों में 17.4 मिलिन है प्रतिशत 10.2 है और 11 प्रतिशत की ऊंचाई तक अनुमानित। विकसित पूँजीवादी विश्व में बेरोजगारों की कुल संख्या 34 मिलियन है।

भारी मंदी में आ रहे नए रुझान : पूंजीवादी समाज में बेरोजगारी में से हमेशा मंदी प्रस्तुत होती है। परन्तु इस समय निम्न विशेष लक्षण हैं। अन्य देशों के साथ जबरदस्त होड़ में तकनीक में परिवर्तन तथा उद्योग के संगठन से जब अर्थव्यवस्था इकट्ठी होती है तो हाथ से निकली छोटी-मोटी नौकरियाँ वापिस नहीं आती। उदाहरण के लिए, अमरीका में पिछले वर्ष के दौरान पुनर्लाभ धीरे-से शुरू हुआ है परन्तु फिर भी रोजगारबहुत अधिक

वार्षिक दर पर % परिवर्तन

	औद्योगिक उत्पादन		जी० डी० पी०		बेरोजगार	
	3 महीने	1 वर्ष	3 महीने	1 वर्ष	ताजा	वर्ष पूर्व
आस्ट्रेलिया	+ 12.4	+ 3.5 फर.	+ 2.8	+ 2.5	10.7 अप्रै.	10.4
बेल्जियम	+ 0.3	+ 0.6 अक्टू.	उ० न.	+ 1.6**	9.7 अप्रै.	8.1
कनाडा	+ 5.4	+ 4.2 फर.	+ 3.5	+ 1.3	11.4 अप्रै.	11.0
फ्रांस	— 11.9	— 2.4 फर.	— 2.0	+ 0.7	10.7 मार्च	10.1
जर्मनी*	— 13.8	— 10.9 मार्च	— 3.3	+ 0.2	8.0 अप्रै.	6.5
हॉलैंड	— 5.1	+ 0.1 फर.	— 0.3	+ 0.5	5.2 अप्रै.	4.4
इटली	— 2.7	— 4.5 फर.	— 2.3	— 0.3	10.4 अप्रै.	10.1
जापान	— 1.2	— 2.2 मार्च	— 0.3	+ 0.2	2.3 मार्च	2.2
स्पेन	— 17.2	— 7.0 फर.	उ० न०	— 0.2	16.5 अप्रै.	15.0
स्वीडन	— 12.2	— 3.7 फर.	— 10.8	— 3.6	7.7 अप्रै.	4.6
स्विट्जरलैंड	— 15.5	— 3.3 क्यू 4	— 1.3	— 0.9	5.0 अप्रै.	2.6
ब्रिटेन	+ 1.1	+ 1.5 मार्च	+ 1.1	+ 0.6	10.5 मार्च	9.4
अमरीका	+ 4.0	+ 3.5 अप्रै.	+ 1.8	+ 2.9	7.0 अप्रै.	7.3

* वार्षिक दर पर पिछले तीन महीनों की औसत से तुलनीय ताजा 3 महीनों की औसत

** जी. एन. पी. : ताजा 3 महीनों की औसत

स्रोत : दी इकॉनोमिस्ट दिनांक : 28 मई 1993

नहीं बढ़ा। यह यू. यन. डवलपमेंट रिपोर्ट 1993 के 'जॉबलेस रिकवरी' में कहा गया है। अमरीकी कम्पनियाँ अपने कर्मियों की छंटनी पर लगी हुई हैं। आज धनाढ्य देशों में उच्च बेरोजगारी दर कम या अधिक स्थायी प्रकृति के रूप में सामने आ रही है। पिछली मंदी में कटौती की मुख्य मार फैक्ट्री कर्मियों पर पड़ी। पर इस बार बैंक से लेकर एडवरटाइसमेंट आदि सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों पर इसकी मार पड़ रही है। याद रहे कि पिछले दो दशकों में इस सेवा क्षेत्र में ही नियुक्तियों को सबसे ज्यादा देखा गया था।

सरकार की विनिमय नीति ने होड़ के लिए संरक्षित औद्योगिक सेवाओं को खुला छोड़ दिया है जिसके परिणामस्वरूप कई नौकरियों में कमी आई है। लिपिकीय कर्मचारियों तथा मध्य प्रबन्धकों के स्थान पर कम्प्यूटर आ रहे हैं। दूसरा लक्षण यह है कि उत्पादन वृद्धि पर है फिर भी रोजगार पीढ़ी ह्रास पर है।

कार्यशक्ति की प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं। यंत्र प्रचालकों तथा लिपिकों की संख्या में बड़ी तेजी से कमी की जा रही है। व्यवसायियों तथा तकनीकीवादियों की संख्या वृद्धि पर है। कुछ ही कर्मचारी पूर्णकालिक रोजगार पाएंगे। अंशकालिक, अस्थायी, अनुबन्ध तथा स्वरोजगार कर्मचारी स्थायी कार्यशक्ति के रूप में बदल जाएंगे। प्रत्येक जगह रोजगारदाता रोजगार संरक्षण नियमों को दूर हटाना चाहता है और वह यह भी चाहता है कि अवैतनिक खर्चे जैसे समाज कल्याण सुविधाएं आदि में पूरी तरह कमी लाई जाए। यही विकास की प्रवृत्ति है।

ग्रेट ब्रिटेन में पांच कर्मियों में से, दो अंशकालिक, अस्थायी या स्वरोजगार वाले हैं। वहीं पर ब्रिटिश सरकार ने वेतन की तुलना में बेरोजगारी लाभ को कम करने के लिए कदम उठाए हैं और इसकी योग्यता की कठोर स्थितियां रख दी हैं। अतः नौकरी विहीन लोग रोजगारदाताओं द्वारा लाई गई स्थितियों को स्वीकारने के अतिरिक्त कहीं नहीं जा सकते।

यूरोप में इस बात पर गंभीर वाद-विवाद चल रहा है कि किस प्रकार कर्मियों को दिए जाने वाले अवैतनिक लाभों को पूरी तरह से समाप्त किया जाय। इण्टरनेशनल हेरल्ड ट्रिब्यून ने अपने 27 मई के अंक में रिपोर्ट दी है कि यूरोपीय समुदाय के नेताओं की आगामी बैठक 21-22 जून को कोपेन हेगन में 'लेबर मार्किट रिफोर्म' विषय पर होगी। इस संबंध में यूरोपीय समुदाय आर्थिक नीति समिति ने पहले से ही नौकरी सुरक्षा की कठोरता को काम करने और मजदूर बाजार में लागतों (कर्मियों के लाभ) की रेखा की पुष्टि कर ली है। रोजगार-दाता यूरोप की समाज कल्याण व्यवस्था और अर्थ-व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन के तर्क देते हैं। यूरोप के कारखानों में वस्तुओं के निर्माण खण्ड में औसत घंटे का वेतन 10.4 डालर था जोकि अमरीका के 1991 के आंकड़ों के 11.23 डालर से कम था। अवैतनिक लागत जैसे बीमा, सेवानिवृत्ति और स्वास्थ्य देख-देख ने यूरोप में एक घंटे के लिए 17.6 कुल मजदूरी लागत अमरीका की 15.45 की तुलना में बढ़ी है। वहीं जापान के घंटे का वेतन 8.39 डालर था और अवैतनिक खर्च 6.20 डालर है। इसीलिए रोजगारदाता 4-6 सप्ताह की वार्षिक अदायगी छुट्टियों सहित अवैतनिक खर्चा क्षीण करना चाहते हैं। इस प्रकार आज पूंजीवादी विश्व का कार्यक्रम कर्मियों के सभी सामाजिक लाभों को समाप्त करने में लगा

हुआ है। वह उन सभी मजदूर संरक्षण कानूनों से मुक्ति पाना चाहता है जिन्हें मजदूरवर्ग ने लम्बे संघर्ष के बाद प्राप्त किया है।

विकासशील विश्व में भी स्थिति बेहतर नहीं है। विश्व विकास रिपोर्ट 1993 में विकासशील पूंजीवादी विश्व की स्थिति का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया गया है: "1960-73 के दौरान विकासशील देशों को जी.डी.पी. में 4.5% वृद्धि का अनुभव है परन्तु रोजगार इससे केवल आधा है।" परन्तु आज उदारीकरण तथा ग्लोबलाइजेशन ने भी अभी तक बहुत कम रोजगार वृद्धि की है।

संपूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था में बेरोजगारी, गरीबी तथा दरिद्रता बढ़ रही है सोवियत संघ द्वारा समाजवाद से पीछे हटने पर पूर्वी योरोप यह दावा कर रहा है कि समाजवाद क्षीण हो रहा है अब केवल पूंजीवाद ही शेष है। और वहां के मजदूरवर्ग व जनता पर भयानक हमले हो रहे हैं। विभिन्न देशों में कामकाजी वर्ग तथा उनके मजदूर संघ इन हमलों को रोकने के लिए अपने प्रयासों में तेजी ला रहे हैं। अभी कई स्थानों पर उन्होंने परिणाम भी प्राप्त नहीं किए न केवल उनकी संगठनात्मक कमजोरियों की वजह से अपितु उनके सुधारवादी नेताओं के कारण जो पूंजीवाद के हिमायती बन गए हैं।

सुस्पष्ट विचारधारा के बिना यह लड़ाई प्रभावकारी ढंग से गठित नहीं की जा सकती जो कि स्वयं में इस संगठन की मजबूती की पहली शर्त है। इसीलिए साथियों, आज विचारों की लड़ाई महत्वपूर्ण लगती है।

फिर भी, पूर्वी जर्मनी के इस्पात कर्मियों की हाल ही की हड़ताल के बारे में उल्लेख करने की आवश्यकता है। उनके द्वारा उठाया गया मामला यह था कि पश्चिम में काम करने वालों के बराबर ही उनका वेतन होना चाहिए। इस हड़ताल में 4 लाख इस्पात तथा धातु कर्मियों ने हिस्सा लिया था। यह 3 मई को शुरू हुई और 3 सप्ताह बाद संपन्न हो गई। हड़ताल के निबटारे में यह माना गया कि अप्रैल 1996 से इस्पात कर्मियों का वेतन पश्चिम जर्मनी के बराबर कर दिया जाएगा। यह उनके लिए मुख्य सफलता है विशेषत: ऐसी स्थिति में जब जर्मनी में गंभीर मंदी की स्थिति बनी हुई है।

मजबूत संगठित विरोध की अनुपस्थिति में मजदूरों के असंतोष व पीड़ा का उपयोग विभाजक एवं फासिस्ट ताकतों द्वारा विश्व के कई हिस्सों में किया जा रहा है। यूरोप में फासिज्म अपना सिर उठा रहा है इसके अतिरिक्त जातीय कलह भी बढ़ रहे हैं। दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी ताकतें इन असन्तुष्टों को विभिन्न इलाकों में कई तरह से प्रयोग में ला रही हैं। मध्य पूर्व तथा मुस्लिम जनसंख्या प्रधान देशों में धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है।

साथियो, अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर हो रही अन्य प्रगतियों में आपका ध्यान एक-दो बातों पर दिलाना चाहूंगा।

ग्लोबीकरण और अर्थव्यवस्था की उदारीकरण के मंच तले अमरीका, जापान तथा यूरोप का नेतृत्व कर रहे जर्मनी जैसे पूंजीवादी केन्द्रों के बीच वास्तव में उग्र व्यापार युद्ध हो रहा है। इनमें से प्रत्येक एक-दूसरे के देश के बीच आयात बाधाएं उत्पन्न कर रहा है जबकि दूसरों को तो वह पूर्ण उदारीकरण सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं। अभी हाल ही में जी-7 देशों की बैठक में अमरीका के नेतृत्व में जी-7 के आपसी सहयोग को पुन: दुरुस्त करने के निर्णय ने भी उनके बीच व्यापार युद्ध के तनाव को कम नहीं किया।

अमरीका अब जापान को चाहता है कि वे तीन वर्ष के अंदर अपना व्यापार अधिक्य 50 प्रतिशत तक काट दे। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्री क्लिंटन ने जापान यात्रा का बीड़ा उठाया है जिसमें वे जापानी व्यापार अधिक्य में कमी लाने के लिए अमरीकी नुस्खा के बारे में विश्वस्त करेंगे। जापान इसे इतनी आसानी से नहीं ले रहा। उन्होंने अमरीकी योजना के विपरीत बदले की कार्यवाही करने का निश्चय किया है। अमरीका व्यापार के मामले जर्मनी तथा फ्रांस के विरुद्ध भी पाबंदियाँ लादना चाहता है। गैट वार्ताएं भी अमरीका के बौद्धिक संपदा अधिकार आदि की हठ के कारण रुकी हुई हैं। इस प्रकार जबकि प्रत्येक उदारीकरण की शिक्षा दे रहा है जिसे वे अपने लिए प्रयोग में नहीं ला रहे।

अमेरीका, विश्व बैंक, आइ.एम.एफ. तथा गैट की समझौता वार्ताओं का प्रयोग अपने आर्थिक संकट के बोझ को दूसरे देशों विशेषत: तृतीय विश्व पर डालने के लिए कर रहा है। तीसरी दुनिया के देशों को कठिन शर्तों पर कर्ज देने के लिए विश्वबैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इन देशों के सम्पदा पर उनका पूरा कब्जा बन सके। साल दर साल बढ़ रहे इन कर्जों के इस बोझ से ये देश कभी भी उबर नहीं पाएंगे।

साथियो,

सीटू ने उन नई नीतियों को भी खुले रूप में छोड़ दिया है जिनका अनुसरण सरकार ने विश्व बैंक के निर्देशों पर किया था। इसके विरुद्ध कामकाजी वर्ग के संगठित प्रतिरोध को चलाने के लिए कदम उठाए भी हैं। फिर भी सरकार हमारे कामकाजी वर्ग सहित जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्से द्वारा दर्ज विरोध की आवाज को नजरअंदाज करते हुए अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही है। ताजा बजट तथा नीतियों को एक साथ लागू करने के प्रयास होने चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोले जा रहे हैं। जिन सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास से सार्वजनिक धन पैदा किया जाता था उसे अब विदेशी तथा भारतीयों के निजी हाथों में दिया जा रहा है। देश के बाहरी ऋण का बोझ आगे बढ़ता जा रहा है और इस ऋण के फंदे में देश डूबता जा रहा है। मिल-बंदी व बीमारी बढ़ती जा रही है जिससे लाखों की तादाद में मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। जीवन की सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम सहनशीलता की सीमा से ऊपर उठ चुके हैं जबकि सरकार दावा कर रही है कि वह दामों की वृद्धि को नियंत्रित करने में सफल हुई है।

देश की एकता तथा अखंडता को साम्प्रदायिक और विभाजक ताकतों से खतरा है। सरकार तथा सत्ताधारी दल उनके विरुद्ध

कदम उठाने में असफल रहे हैं। हिन्दू तथा मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा आक्रामक चुनौतियां दी जा रही हैं। देश के लोगों को जाति एवं धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। यह कामकाजी वर्ग की एकता को भी तोड़ता है। अतः सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई करना ही हमारा पहला कार्य बनता है। सारी स्थिति पर विचार करने के बाद सीटू इन नीतियों के विरुद्ध एक मजबूत और विशाल जंग छेड़ने के लिए कदम उठाएगा। इसके आधार पर मजदूर संघों की स्पानसरिंग कमेटी ने किसानों, कृषि मजदूरों, युवाओं, और विद्यार्थियों, औरतों तथा वैज्ञानिक कर्मियों आदि के जन-संगठनों से बातचीत करके इन नीतियों के विरुद्ध लड़ाई के लिए प्रतिरोध के विशाल मोर्चे में हिस्सा लेने के आह्वान की पहल की है। अभी तक हमारा संघर्ष नगरों तथा शहरों तक सीमित था। अब यह देश के सभी गांवों तथा लोगों के सभी सामाजिक वर्गों को साथ लेकर चल रहा है। यह अपने आप में एक नई उपलब्धि है कि कामकाजी वर्ग सांप्रदायिकता के खतरों तथा उन पश्चगामी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए समाज के सभी वर्गों को इकट्ठा कर रहा है जिसने हमारी खून-पसीने से मिली स्वतंत्रता से समझौता किया है - 15 अप्रैल को नई दिल्ली में हुई सभा में सारी स्थिति पर नजर डाली गई और गम्भीर बातचीत के 'सांप्रदायिकता तथा सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध जन-संगठनों का मंच' तैयार करने का निश्चय किया गया। बीस सूत्रीय मांग-पत्र ग्रहण करने के अतिरिक्त सभा ने 9 सितबर की विशाल हड़ताल तथा बन्द को चरम सफलता दिलाने के लिए जोरदार कार्यक्रम चलाने का निश्चय किया है। मैं जानता हूं कि हमारी राज्य समितियाँ सभा द्वारा पारित कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के कदम उठा रही हैं।

यद्यपि आप सभी इस निर्णय के महत्व को जानते हैं तो भी मैं दुबारा बन्द तथा हड़ताल की प्रचार पहल के महत्व पर जोर डालना चाहूंगा। सरकार अपने प्रचार मशीनरी के जरिए तथा बुर्जुवा प्रेस द्वारा देश में किए जा रहे प्रचार के बल पर जनता को काफी हद तक भ्रमित करने में सफलता प्राप्त कर रही है। अतः यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम प्रत्येक नागरिक से सम्पर्क करें तथा देश द्वारा सामना किए जा रहे खतरों के सारे पक्षों को सही ढंग से बताएं। कार्य इस प्रकार संगठित होना चाहिए कि सभी गांवों तथा शहरों में पहुंचा जा सके। एक समिति बनाई जाएगी जिसमें सभी जन-संगठनों से संबंधित सदस्य होंगे। राज्य अनुसार तथा जिला अनुसार प्रचार साहित्य दिया जा रहा है और प्रचार अभियान सामान्य चुनावों की भांति चलाया जाएगा। इस महान लड़ाई में लोगों को सक्रिय बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सभी सभव तरीके जैसे पर्चे, पोस्टर, सिनेमा स्लाइड, लेख आदि प्रकाशित किए जाएंगे। हमें यह भी अवश्य देखना होगा कि नई दिल्ली सभा में की गई घोषणा प्रत्येक घर तक पहुंचे। यह लड़ाई देश के उद्धार के लिए है, यह लड़ाई कामकाजी वर्ग तथा लोगों के बहुत बड़े वर्ग के लिए है। इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अपेक्षित संगठनात्मक गारंटी पर भी विचार करना होगा। हमारी राज्य तथा जिला स्तरीय समितियाँ इन गतिविधियों पर दिन प्रतिदिन निगरानी रखेंगी। यदि हम इसे प्रभावकारी रूप से आयोजित करने में सक्षम होते हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम सरकार को इन नीतियों के वापस लेने के लिए जोर डाल सकते हैं नहीं तो यह भी हो सकता है कि हम यह सरकार ही बदल दें।

हमें इस तथ्य पर भी ध्यान देना होगा कि कई स्थानीय तथा खण्डीय विषय सामने आ रहे हैं। इसके विरुद्ध हमें खण्डीय तथा स्थानीय कार्यवाही को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उदाहरण के लिए मिलबंदी व रुग्णता के विरुद्ध लड़ाई। हमें राष्ट्रीय तथा राज्य अनुसार सभाएं भी करनी होंगी जिसमें कार्यवाही के कार्यक्रम पर निश्चय किया जाएगा। इसे 9 सितम्बर के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भी मनाया जा सकता है। साम्प्रदायिकता के विरुद्ध भी इसी प्रकार के प्रयास करेंगे।

विघटनकारी तथा साम्राज्यवादी एजेन्सियां देश को कई तरह से अस्थिर करने पर लगी हुई हैं। बम्बई तथा कलकत्ता के हमले उनके ताजा प्रयास हैं। इस प्रकार के साम्राज्यवादी साजिशों को भी मजदूर वर्ग द्वारा पूरी तरह बेनकाब करना होगा।

बजट के बाद सरकार कष्ट साध्यता के प्रस्तावों को आगे बढ़ा रही है। इस संबंध में 10वें वित्त आयोग तथा योजना आयोग की बातचीत मजदूर संघों से हुई है। उनमें से कई का सीटू ने कड़ाई से विरोध किया है। एन.डी.सी. द्वारा योजना और कार्यक्रम के रूप में चार मंत्रियों कल्याण सिंह, भजनलाल, ग्योंग अपांग तथा केन्द्रीय मंत्री एच. आर. भारद्वाज सहित उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री बीजू पटनायक की अध्यक्षता में एक मंत्रीय समिति नियुक्त की गई है। कई क्षेत्रों को अपनाने का 17 बातों का प्रस्ताव सामने आया है। मैं यहां सभी प्रस्तावों की बात नहीं करना चाहता। पहले यह समिति संसाधनों को सक्रिय बनाने के लिए कह रही है अमीरों के लिए कर में कमी की सरकार की नीति तथा कर चालकों को प्रोत्साहित करना, आज जानी-पहचानी सच्चाई बन गया है। कुल योजना में जो समानांतर काली अर्थव्यवस्था ने छेद कर रखा है वह भी उन्मुक्तता से जारी है। साल दर साल वित्तमंत्री सरकारी खजाने में पैसा लाने की योजनाओं की घोषणा करते हैं। किसी भी योजना के उचित प्रभाव नहीं रहे। हाल ही में श्री मनमोहनसिंह ने गोल्ड बॉन्ड योजना पेश करने की घोषणा की है जो कि वैध पैसा मालिकों की अपेक्षा काला धन रखने वालों को अधिक छूट देती है। सरकार ने अपने बजट तथा अन्य नीतियों के माध्यम से पूँजीपतियों को कई प्रकार से छूट दी है। इसी समय वे आय-उपार्जकों पर कष्टसाध्यता के नाम पर हमला करना चाहते हैं। प्रस्तावों में केन्द्र एवं राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पर रोक, सब्सिडी आदि में कटौती भी शामिल किया गया है। प्रस्तावों में तीसरी बात कही गई है कि "एक साल की अवधि तक केन्द्र तथा राज्य में कोई और अतिरिक्त महंगाई भत्ता

नहीं दिया जाएगा...।" महंगाई भत्ते से संबंधित यह नीति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समान आयोजित निजी क्षेत्रों पर भी लागू होगी। सरकार में इस अवधि के दौरान आय संशोधन भी नहीं होंगे... । हाल ही में चल रहे महंगाई भत्ते के सूत्र की जांच होगी। सरकारी कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जाएगा। सेवानिवृत्त होने के समय छोड़कर अर्जित अवकाश न इस्तेमाल करने के बदले पैसा देना बंद कर दिया जाना चाहिए। घरेलू यात्रा से अतिरिक्त एल.टी.सी. को भी बंद कर दिया जाना है। यह सुझाव पिछले वर्ष के दौरान कर्मियों के असली वेतन की वास्तविक कमी की पृष्ठभूमि पर देखे जा सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के 1 मई 1993 के संपादकीय लेख में उनके अनुसंधान ब्यूरो द्वारा किए गये अध्ययन के परिणाम इस प्रकार दर्शाए गये हैं :

"संगठित निजी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा अर्जित किए गये वेतन में उत्पादन मूल्य तथा जोड़े गए मूल्य के हिस्से में 1986-87 से ह्रास दर दिखाई पड़ रही है। परन्तु असली तेज गिरावट 1991-92 में आई। इस प्रकार जबकि निजी संगठित क्षेत्र के कुल उत्पाद मूल्य में वेतन का हिस्सा 1986-87 के 12.0 प्रतिशत से 1990-91 के 10 प्रतिशत पर गिरा है, 1991-92 में यह 8.7 प्रतिशत तक चला गया। इनके वेतन के अनुपात 12.1 प्रतिशत, 10.2 प्रतिशत और 1991-92 में 7.8 प्रतिशत था। वेतन अर्जक वर्ग को मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक आय में भारी क्षति हुई है। नाममात्र की वेतनवृद्धि की अपेक्षा उपभोक्ता मूल्य सूची में 4 प्रतिशत के लगभग अधिक उठाव आया है। दूसरे शब्दों में जोड़े गये मूल्य में आय के हिस्से में ह्रास हुआ है जो असली वेतन में ह्रास के कारण होता है। इस रुख का कारण मजदूरों और कर्मचारियों से संबधित नहीं है बल्कि उद्योग तथा सरकार के लिए है।"

आगे : "284 मुख्य कम्पनियों के नमूना अध्ययन दिखाते हैं कि 1991-92 के दौरान इन कम्पनियों की अपनी लागत 12 प्रतिशत तक चली गई जो असलियत में ह्रास दिखाती है जब मुद्रास्फीति की दर उस वर्ष 15 प्रतिशत की दर के आस-पास थी। जबकि मंदी व मुद्रास्फीति की इन परिस्थितियों के बावजूद शुद्ध बिक्री धड़ाके से 24 प्रतिशत तक चली गई। ये प्रवृत्तियां संगठित औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक वृद्धि की प्रवृत्ति पर टिप्पणी करती हैं। इन्होंने संगठित औद्योगिक क्षेत्र में हाल ही में स्थान लिया है जिससे औद्योगिकीकरण की पूंजीवादी सघनता प्रक्रिया ने रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं की है। वेतन या तनख्वाह की आय दबाव के नीचे आ गयी है। इस तथ्य के बावजूद पिरामिड के ऊपर के निजी संगठन के क्षेत्र इतना बुरा नहीं कर रहे। ऐसा लगता है कि सातवीं योजना की वृद्धि के सुधार के फल न्याय संगत ढंग से नहीं बांटे गये।"

अल्पव्ययता वाले प्रचारकों को समझना चाहिए कि देश के वेतन अर्जक महज बैठकर खानेवाला नहीं है। वे अपने खून-पसीने से इस देश के लिए धन पैदा कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर वर्णित अध्ययन यह साबित करते हैं कि संपूर्ण 7वीं योजना अवधि में उनका हिस्सा ह्रास की प्रवृत्ति को दर्शाता है। सभी लोगों की ओर से मैं समझता हूं श्री पटनायक यह अच्छी तरह समझेंगे कि दामों के बढ़ने के कारण वेतन की कमी की भरपाई के लिए महंगाई भत्ते को रखना चाहिए। इसीलिए महंगाई भत्ते में जाम वेतन कटौती के अतिरिक्त और कुछ नहीं। बहरहाल, देश का कामजी वर्ग इसका विरोध पूरी शक्ति से करेगा।

साथियो, इस संबंध में मैं आपके सामने कुछ मजदूर संघों के नेताओं का रवैया रखना चाहूंगा जो बिलकुल मजदूरों के हित के विरुद्ध जाता है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की हाल ही में हुई बैठक में नेशनल फैडरेशन ऑफ टेलिकम कर्मचारियों के महा-सचिव श्री ओ. पी. गुप्ता ने लिखित वक्तव्य में सुझाव दिया है गलत किए गए महंगाई भत्ते के प्रस्ताव का 'विरोध' के साथ स्वीकार करेंगे। उन्होंने बी. टी. ई. एफ. (बी. एम. एस.) तथा एफ. एन. टी. ओ. के साथ 4 मई 1993 को टेलिकम में व्यवस्था पुनर्गठन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बारे में टेलिकम टेक्नोक्रैट श्री पितरोदा ने टाइम्स आफ इण्डिया में एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने दावा किया कि : 'अगले दस वर्ष तक और अधिक लोगों के आने पर लोग लगाने पर टेलिकॅम मजदूर नेताओं के साथ हुए समझौते के साथ एक नई शुरुआत हो चुकी है। जबकि 2000 ईस्वी तक टेलीफोनों की संख्या पांच मिलियन से 20 मिलियन अर्थात् चौगुनी कर दी जाएगी। इसके लिए टेलिकॅम के पुनर्गठन की आवश्यकता है।' इस पुनर-गठन के समझौते के अनुसार 210,840 कर्मियों में से 61028 पदों को समाप्त कर दिया जाएगा जिसमें से 31,700 पद पैदा किए जाएंगे और 29320 कर्मियों का अधिक्य होगा। अतः यहां न केवल नई भर्ती नहीं होगी अपितु फालतू कर्मियों को भी बाहर निकाला जाएगा। यही है मनमोहनसिंह जी का मजदूरों के लिए सुरक्षा कवच।

आप सभी अवश्य जानते होंगे कि भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में लम्बे समय से पड़ी हुई वेतन समझौता वार्ताओं को चलाएगी। जुलाई 1992 में तय की गई महंगाई भत्ता समिति का प्रस्ताव भी सरकार ने दरकिनार कर रखा है। इनको तथा कुछ अन्य मांगों को उठाते हुए केन्द्रीय सार्वजनिक मजदूर संघों (सी.पी.एस.टी.यू.) ने अप्रैल के महीने में किसी भी समय 72 घंटे की हड़ताल करने का निश्चय किया था। हड़ताल के लिए शानदार तैयारी की गई थी और कर्मियों की प्रतिक्रिया भी बहुत अच्छी थी। इसने अधिकारियों को परेशानी में डाल दिया और इंटक को मैदान में उतारा गया उन्होंने लगभग इन्हीं मांगों को उठाते हुए 16 मार्च को हड़ताल की धमकी दी।

श्रम मंत्री श्री संगमा का इंटक के नेताओं के साथ विचार-विमर्श का नाटक हुआ और अंत में वे एक 'समझौते' पर सहमत हुए। समझौते के अनुसार समझौता वार्ताओं से प्रतिबंध उठाया जा रहा है और महंगाई भत्ता समिति के 2 रुपये प्रति बिन्दू का प्रस्ताव आल इंडिया कन्ज्यूमर प्राइस इण्डेक्स के 1960 के क्रम के 800 बिन्दू से ऊपर मान लिया गया और यह भी सहमति हुई कि 1-1-89 से यह शुरू माना जाएगा। जिस हड़ताल को होना ही था उसे वापिस लिया गया। सी. पी. एस. टी. यू. ने

महंगाई भत्ते तथा जिन मामलों पर मंत्री समझौता करने को सहमत हुए थे के प्रश्न की अनियमितताओं को दूर करने के लिए दुबारा बात करने को मजबूर किया गया। तब सी.पी.एस.टी.यू. ने हड़ताल को स्थगित किया। श्री संगमा और इंटक के नेता अभी तक इस सोच में हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मी इस बनावटी लड़ाई की चाल को समझने में सक्षम नहीं हैं। आगे मैं आपको सार्वजकिक क्षेत्र की समझौता वार्ताओं के सरकार के निर्देश कि यह अतिरिक्त लागत के बिना होना चाहिए के बारे में बताना चाहूंगा। हमें इस पूर्व शर्त को ठुकराना होगा।

खबर है कि श्रममंत्री मजदूर बाजार सुधारों के अपने कार्यक्रम को लेकर तैयार हैं जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन। इस संशोधन के जरिए मजदूरों को हटाकर बाहर निकालने की प्रक्रिया में सुविधा लाने और सरकार की आज्ञा बिना मालिक द्वारा कभी भी अपनी इच्छा से उद्योग को बन्द करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया जा रहा है। इसका अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं। नई योजना में मालिकों को भारी मुनाफा लूटने देने की आजादी ही सर्वोपरि है उसके बदले चाहे कितनी ही नौकरियां समाप्त हों उसकी कोई परवाह नहीं।

यह रिपोर्ट है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संसदीय रेलवे कन्वेंशन कमेटी की सिफारिशों के विरुद्ध तीस 6000 हार्स पावर वाले बिजली के इंजनों को एक स्वीडन की कम्पनी एशिया ब्राउन बोवेरी से खरीदने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है। है। समिति ने विस्तृत अध्ययन करने के बाद रेलवे की चित्तरंजन कार्यशाला द्वारा विकसित 5000 हार्स पावर वाले बिजली के इंजनों की सिफारिश की थी। समिति ने टिप्पणी की थी यदि महंगे 6000 हार्सपावर इंजनों को प्रयोग करना है तो विशाल पूंजी लगाकर हमें रेल लाइनों को बदलना होगा।

इसीलिए सरकार को ए.बी.बी. के प्रस्ताव की ओर जाना चाहिए। 'हिन्दू' दैनिक की दिनांक 2 जून 1993 के अनुसार चित्तरंजन वालों की लागत 7 करोड़ रुपया है जबकि आयातित प्रति इंजन की कीमत 25 करोड़ होगी। यहां इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि इंजनों को आयात करने का निर्णय किस तकनीकी निर्धारण या रेलवे की आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर किया गया है। यह सरकार जो खर्च घटाने की बात करती है इस मामले में तो लागत मूल्य की बात को बड़ी आसानी से भूल गई। जबकि हमारे रेलवे की अपनी फैक्ट्री इन मांगों को पूरा कर सकती है फिर भी सरकार विदेशी इंजनों के पीछे जा रही है। यह विश्व बैंक का नया निर्देश है जिसके लिए हमें अपनी तकनीकी निपुणता तथा ढांचागत सुविधाओं को छोड़ना होगा।

सभी मजदूर संघों के विरोध के बावजूद सरकार भारतीय लोह तथा इस्पात कम्पनी (इस्को) का निजीकरण करने जा रही है। 16000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति केवल 134 करोड़ रु. एक में निजी कम्पनी मुकुन्द को हस्तांतरित की जा रही है जिसके पास इस्पात उत्पादन का कोई अनुभव ही नहीं है। कम्पनी के आधुनिकीकरण के लिए निजीकरण का बहाना लगाया जा रहा है। आधुनिकीकरण आवश्यक हैं। परन्तु इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को आसानी से सौंपा जा सकता है जिसे इस क्षेत्र में विश्वसनीय अनुभव भी है। सेल प्राधिकरण ने भी इसे अपने हाथ में लेने की इच्छा प्रकट की है बशर्तें सरकार उन्हें इसकी आज्ञा दे। कम्पनी आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक 3000 करोड़ रु. की राशि सेल द्वारा दी जा सकती है। परन्तु वित्तमंत्री तथा सरकार इसे निजी पूंजीपतियों को हस्तांतरित करना चाहती है। जिसके पीछे का कारण फिर एक रहस्य बना हुआ है।

साथियो,

कांग्रेस (आई) सरकार द्वारा उपरोक्त तथा दूसरी नीतियों के पीछे भागने के विरुद्ध मजदूर वर्ग को इकट्ठा होकर पूरी शक्ति से लड़ना होगा। आज मजदूर संगठनों के आन्दोलन की एकता की अत्यंत आवश्यकता है। जो मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा में आगे नहीं आते उनकी सही ढंग से आलोचना करते हुए हमें इस एकता को कायम करने के लिए पुरजोर प्रयास करना होगा। सामूहिक प्रयासों से स्थापित विशाल मोर्चा को और मजबूत बनाना होगा।

समाप्त करने से पूर्व मैं त्रिपुरा के लोगों को अवश्य बधाई दूंगा जिन्होंने 3 अप्रैल 1993 को हुए विधान सभा के चुनावों में कांग्रेस (आई) को चारों ओर से शिकस्त दी है। त्रिपुरा में वाम मोर्चे की ऐतिहासिक विजय देश के लोकतांत्रिक आन्दोलन को आगे शक्ति प्रदान करेगी। मई में हुए उप चुनावों में लोगों ने कांग्रेस (आई) को फिर नकार दियाहै। यह किसी कांग्रेस (आई) शासित प्रदेश में लोगों द्वारा दी गई बहुत बड़ी मात है। उनके विश्व बैंक के साथ अक्षम्य समझौतों, ऊपर से नीचे तक फैले भ्रष्टाचार, रामास्वामी के भ्रष्टाचार के मामले में उनका रवैया, देश की धर्मनिरपेक्ष संरचना की सुरक्षा में उनकी असफलता, सांप्रदायिक दबाव के आगे घुटने टेकना आदि बातें लोगों के दिमाग में थीं जब वे मत डालने गये। मैं आप सभी की ओर से कांग्रेस (आई) को शिकस्त दिलाने के लिए उन्हें बधाई देता हूं।

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के परिणामों ने देश में वाम आन्दोलन की प्रतिष्ठा को ऊपर उठाया है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने वाम मोर्चे में अपनी आस्था प्रकट की और इसे जोरदार सफलता दी। मैं आप सभी की ओर से पश्चिम बंगाल के लोगों तथा वाम मोर्चे को बधाई देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

धन्यवाद!

सीटू ने संगठनात्मक रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया
समाजवाद की महत्वपूर्ण भूमिका दोहराई गई

जीवन रॉय

4-6 जून, 1993 को हुई भुवनेश्वर कार्यसमिति की बैठक में संगठनात्मक रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया गया। आशा है कि कार्यसमिति में सुझाये गये संशोधनों को शामिल करने के बाद सचिवमंडल अगले माह तक रिपोर्ट को जारी कर देगा। यह संगठनात्मक दस्तावेज संगठन के विभिन्न स्तरों पर हुए विचार-विमर्श का परिणाम है। जैसा कि 19-21 फरवरी, 1993 में बंगलौर में हुई जनरल काउंसिल बैठक में सुझाव दिया गया था कार्यसमिति ने रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने से पहले विभिन्न राज्य समितियों के सुझावों व संशोधनों पर विचार किया व उनमें से अनेक को रिपोर्ट में शामिल किया।

यह एक अच्छी बात है कि अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के दो वर्ष पहले सीटू एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक दस्तावेज को प्राप्त कर सकी। इससे सीटू रैंक की लम्बे समय से चली आ रही एक मांग पूरी होगी। संभवतः सीटू की स्थापना के बाद से यह पहला अवसर है जब सीटू ने अपने संगठन के प्रश्न पर इतना व्यापक विचार-विमर्श किया, संगठन की वर्तमान स्थितियों का विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण किया तथा विस्तार एवं सामाजिक-आर्थिक अवस्थाओं से जुड़ी जटिलताओं से व समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक सुझाव दिये।

रिपोर्ट की मूल दिशा

कार्यसमिति ने सभी सम्बद्ध यूनियनों व राज्य समितियों से अपील की है कि वे सभी स्तरों पर अपने काम-काज को रिपोर्ट में निर्धारित दिशा में केन्द्रित करने का कार्य आरंभ करें, रिपोर्ट में (क) कामकाज की कमियों, (ख) उन कमियों का मूल कारण (ग) उन्हें दूर करने का तरीका (घ) सुझाव समेत सभी विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में जिस संगठनात्मक रुख की अपेक्षा की गयी है उसकी केवल रूपरेखा पर विचार किया गया है।

अपने स्थापना सम्मेलन के बाद से सीटू का लगातार विस्तार हुआ है। इसकी सदस्यता का आधार 8 से 25 लाख हो गया। वास्तविक अर्थ में इसका प्रभाव कई गुना अधिक रहा। इस अवधि में हमारे देश का कोई दूसरा श्रम संगठन इस गति से प्रगति नहीं कर सका। लेकिन बारीक विश्लेषण से पता चलता है कि अन्तिम दस वर्षों में संतुलित विस्तार की रफ्तार अपेक्षाकृत कम रही। सदस्यता के विवेचन से पता चलता है यह विस्तार असंगठित क्षेत्र में अधिक हुआ है वहां भी यह विकास के अनुरूप नहीं रहा है।

यह सम्भावना है कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था के चहुमुखी अवस्वरण, कंम्प्यूटरीकरण की बढ़ती हुई रफ्तार तथा ठेका प्रणाली में वृद्धि का संगठित व मूल क्षेत्र में श्रम संगठनों की सदस्यता पर विपरीत असर पड़ेगा। सीटू के मामले में ऐसा नहीं था क्योंकि सदस्यता का मूल आधार ही बहुत अधिक नहीं था।

लिहाजा यह महसूस किया गया कि जब तक सभी क्षेत्रों में सदस्यता नहीं बढ़ाई जाती तथा थोड़े से अन्तराल में उसके गठन में सुधार नहीं लाया जाता तब तक सीटू के लिए देश के एक प्रमुख श्रम संगठन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करना अत्यन्त कठिन होगा।

लेकिन यह मानना उचित नहीं होगा कि भारत में श्रम-संगठन का वर्तमान स्तर है उसमें अकेले सीटू के कुछ विकास से मजदूर वर्ग को जागृत किया जा सकेगा कि वह वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का मुकाबला कर सके। अतः रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है थोड़े समय में ही सीटू का विकास किया जाये तथा साथ ही सम्पूर्ण मजदूर वर्ग में एकता स्थापित की जाये। संगठित मजदूर आन्दोलन को ऐसी ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए कि वह जनता तथा अपने ऊपर होने वाले हमलों का प्रभावशाली ढंग से जवाब दे सके, संचार व राजनीति के अपराधीकरण का प्रत्युत्तर दे सके तथा राष्ट्रीय एकता व स्वाधीनता की रक्षा करने वाली प्रमुख शक्ति के रूप में उबर सके।

श्रम संगठनों की एकता

लिहाजा, रिपोर्ट का सबसे अधिक बल श्रम-संगठनों की यथासंभव व्यापक एकता पर है। बेशक, सीटू को मजबूत बनाने का मुद्दा सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि वर्तमान समय में इस उद्देश्य को प्राप्त करने में वही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

श्रम-संगठनों की एकता के प्रश्न पर कार्यसमिति ने अपनी सम्बद्ध यूनियनों से—जो मजदूर एकता में वाकई विश्वास रखती हैं—अपील की है कि वे संगठित मजदूर आन्दोलन के विचार को आगे बढ़ाने के लिए अभियान चलायें जो कि पूर्ण एकता से पहले का एक कदम होगा। ऐसे परिसंघ का गठन विभिन्न श्रम संगठनों की पहचान को कायम रखते हुए किया जा सकता है तथा फैसलों का आधार सर्वसम्मत निर्णय होगा।

ग्रास रूट स्तर पर श्रम संगठनों की एकता को बढ़ाने के लिए कार्यसमिति ने एक उद्योग—एक यूनियन पर पुनः विचार किया है। कार्यसमिति का मत है कि मजदूर वर्ग की संगठित व जुझारू गतिविधियों से सम्पूर्ण एकता की परिस्थितियां स्वतः विकसित होंगी। इस बीच जहां कहीं संभव हो राज्य समितियां एक यूनियन बनाने पर विचार करेंगी। ऐसे विलय के मूल सिद्धांत की रक्षा की जानी चाहिए यानी मजदूर हितों व

श्रम-संगठनों के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

संगठनात्मक रिपोर्ट में एक उद्योग में कार्यरत विभिन्न फेडरेशनों को एक बैनर तले लाने पर भी विचार किया गया है। कार्यसमिति ने नोट किया कि वर्तमान समय में ऐसे फेडरेशन व समन्वय समिति काफी संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं। कार्यसमिति ने विभिन्न फेडरेशनों के विलय की बात कुछ निश्चित शर्तों के आधार पर कही।

रिपोर्ट व विचार-विमर्श में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने प्रायोजक समिति में मजदूर सगठनों का यह संयुक्त मंच मजदूर वर्ग की गतिविधियों का परिणाम है, जिसने 9 सितम्बर के भारत बन्द का आह्वान किया है। रिपोर्ट में सम्बद्ध व भिन्न श्रम संगठनों से अपील की गयी है कि वे जन संगठनों की इस एकता को निचले स्तर तक ले जायें तथा संयुक्त समितियाँ बनाएं।

विस्तार व गठन

रिपोर्ट में अपील की गई है कि जिन क्षेत्रों में सीटू का विस्तार हो चुका है वहां इसकी गतिविधियों को और सुदृढ़ बनाया जाये। इससे इसके विकास में मदद मिलेगी। अनेक साथियों ने महाराष्ट्र, कर्नाटक व गुजरात जैसे इलाकों में मौजूदा ठहराव को तोड़ने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

इसी प्रकार हिन्दीभाषी क्षेत्रों में संगठन के विस्तार को भी रिपोर्ट व विचार-विमर्श में प्रमुख स्थान मिला।

सदस्यों ने मूल औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवेश के लिए बेहतर रणनीति की बात कही तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने की बात को सबसे ज्यादा महत्त्व दिया। संगठन को असंगठित क्षेत्र व ठेका मजदूरों के बीच मजबूत बनाया जाना चाहिए जिनकी कार्यस्थितियां अभी भी अर्ध-दासता की सी हैं।

सामाजिक नेता के रूप में भूमिका

रिपोर्ट में इस बात पर विचार किया गया है कि हिन्दीभाषी क्षेत्रों में संगठन कमजोर रहा है। निरन्तर अर्ध-सामंतवादी सामजिक-आर्थिक वातावरण इन क्षेत्रों में हर लोकतांत्रिक गतिविधि पर हावी रहा है। इस बंधन से उबरे बिना सीटू आन्दोलन बहुत दूर तक नहीं जा सकता। जाति-भेद व सांप्रदायिक समस्याएं इस हद तक हैं कि वे वर्ग-एकता में आड़े आ रही हैं। रिपोर्ट तथा विचार-विमर्श में किसान व भूमि सुधार आन्दोलन में सीटू की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष बल दिया गया है। जैसे ही श्रम-संगठन किसानों की समस्याओं तथा काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने जैसे मुद्दों को लेकर आगे आयेंगें वैसे ही मजदूर वर्ग का लोकतांत्रिक आन्दोलन और मजबूत बनेगा।

यह आम राय है कि जब तक सीटू शुद्ध श्रम-संगठन की सीमाएं नहीं तोड़ती तब तक सीटू नेतृत्वकारी श्रम-संगठन की भूमिका को कायम नहीं रख सकती।

अपना वैचारिक व सांस्कृतिक पुनर्गठन करके ही हमारे संगठन अपनी नेतृत्वकारी भूमिका कायम रख सकते हैं। अधिकतर साथियों ने इस बात पर बल दिया कि श्रम-संगठन गतिविधियों का इस प्रकार पुनर्गठन किया जाये कि वे मजदूर वर्ग के परिवारों की आर्थिक व सांस्कृतिक समस्याओं को उठा सकें।

नेतृत्व व मजदूरों के बीच तालमेल सुधरे

संगठनात्मक विचार-विमर्श में नेतृत्व के पुनर्गठन का मसला महत्वपूर्ण रूप से उभर कर आया। अनेक सदस्यों ने इस मत का समर्थन किया कि अधिक से अधिक मजदूरों को नेतृत्व में लाया जाये।

लोतांत्रिक कार्य-प्रणाली

विचार-विमर्श में रिपोर्ट में उल्लिखित लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली पर विशेष बल दिया गया है। आम अनुभव यह है कि इस दिशा में जो भी प्रयास किया गया वह सही अर्थ तक नहीं पहुंचा। यह एक ढर्रे जैसा कार्यक्रम होकर रह गया। सामूहिक विचार-विमर्श व अर्थपूर्ण कार्यविभाग का अभाव योजनाबद्ध रिपोर्टिंग व्यवस्था का अभाव, यूनियनों के सम्मेलन आयोजित करने में अनियमितता आदि सभी अफसरशाही ढर्रे के लक्षण हैं। यह सूची कितनी ही लम्बी हो सकती है। जब तक हमारा आन्दोलन पूरे श्रम-संगठनों के आन्दोलन पूरे श्रम-संगठनों में लोकतंत्र के आधार को सही रूप नहीं दे पायेगा तब तक महज एक औपचारिका ही रहेगी, ऐसी स्थिति में नेतृत्व व फैक्ट्री के बीच सही तारतम्य नहीं बैठ पायेगा। सक्रियता का अर्थ है मजदूरों को रोजमर्रा के काम-काज में तथा फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल करना है

नेतृत्वकारी समितियों की भूमिका

भुवनेश्वर कार्यसमिति की बैठक में कार्यसमिति व सीटू यूनियनों के पदाधिकारियों के चुनाव की पद्धति पर भी विचार किया गया है, यह कहा गया है कि विभिन्न यूनियनें अपने संविधान के अनुसार चुनाव करें तथापि, यह बात गंभीरता से महसूस की गयी कि नेतृत्व इस बात को देखे कि सम्मेलन के बाद थोपने वाला भाव न रहे। संभावित समस्याओं से उभरने के लिए कार्यसमिति ने गुप्त मतदान की व्यवस्था को पसन्द किया।

भारत में मजदूर आन्दोलन की सबसे बड़ी कमी नेतृत्वकारी केन्द्र की भूमिका में कमी है। यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि सुधारवादी श्रम-संगठनों के सम्बद्ध घटक अपने रोजमर्रा के कामकाज में स्वयंभू अंदाज में काम करते हैं। वे संगठित अपीलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते।

नेतृत्वकारी केन्द्र के काम-काज की दृष्टि से सीटू की स्थिति बेहतर है। राज्य समितियां कुल मिलाकर काम कर रहीं हैं। राज्य व सम्बद्ध यूनियनों के बीच जिला समितियों ने ग्रास रूट स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की है। औद्योगिक फेडरेशनों व संगठनात्मक नेतृत्व के स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की

है। औद्योगिक फैडरेशनों व समन्वय समितियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त सीटू केन्द्र सभी स्तरों पर वैचारिक व संगठनात्मक नेतृत्व के लिए जिम्मेदार है। संगठनात्मक रिपोर्ट के मसौदे में गहरी आत्मालोचना की गई है व पूर्ण बदलाव की आवश्यकता बताई गई है। विचार-विमर्श के बीच अनेक नये मुद्दे उभर कर आये। कार्यसमिति ने सुझाव दिया है कि सामूहिक कार्य एक-सी समझ विकसित करने व नये कैडर को नेतृत्वकारी भूमिकाओं में लाकर बेहतर काम-काज को सुनिश्चित किया जा सकता है। इस सबके अतिरिक्त किसी भी नेतृत्वकारी समिति की प्राथमिक भूमिका यह होगी कि वह यह देखे कि उससे नीचे की समितियां संगठनात्मक रिपोर्ट पर ठीक से अमल करें।

विचार-विमर्श के दौरान नेतृत्वकारी समितियों को सालभर सक्रिय रखने की परेशानी भी उभरकर आयी। सत्ताधारी दल की आपसी दुश्मनी के अलावा आर्थिक समस्या भी है। अनुभवी कैडर की कमी हर जगह है। यह मांग की गई कि मजबूत केन्द स्थायी रूप से मदद करे।

कैडर प्रशिक्षण

पूरे विचार-विमर्श के दौरान राज्यों, औद्योगिक फैडरेशनों व केन्द्रीय स्तर पर कैडर प्रक्षिशण की सांस्थानिक व्यवस्था की मांग उभर कर आयी। सचिवमंडल ने आश्वासन दिया कि उसके पास जो भी संसाधन हैं उनके आधार पर केन्द्रीय स्तर पर कैडर प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जायेगा। वह देखेगा कि तीन माह के भीतर एक सिलेबस जारी किया जा सके। तथापि, कोई भी कैडर प्रशिक्षण अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता यदि यह कैडर को नेतृत्व की स्थिति में नहीं लाता।

वैचारिक सम्पर्क

संगठन के निर्माण में वैचारिक आधार को आवश्यकता पर अध्यक्ष का उद्घाटन भाषण तथा महासचिव के समापन भाषण में बल दिया गया।

सीटू के अध्यक्ष ने इस बात पर बल दिया कि जब तक एक ओर विचारधारा और संगठन व दूसरी संगठन में पूरा तालमेल नहीं होता तब तक कोई संघर्ष अपने अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच सकता। उन्होंने कहा कि यूरोप, अमरीका व जापान में श्रम-संगठन बढ़ती हुई बेरोजगारी व रोजगार कटौती के खिलाफ आम विरोध में शामिल हो रहे हैं। तथापि, उन्होंने कहा, कि ये संघर्ष पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि नेतृत्व पूँजीवाद समर्थक ही है। महासचिव ने अपने समापन भाषण में वैचारिक काम-काज को संगठन निर्माण से जोड़ने के महत्व पर बल दिया। का. पंधे ने स्पष्ट किया कि जब तक सीटू के संविधान के मुताबिक समाजवाद के उद्देश्य को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता तब तक रिपोर्ट में शामिल वर्ग एकता, संगठन के लोकतांत्रीकरण तथा लोकतांत्रिक आन्दोलन में मजदूर वर्ग की प्रमुख भूमिका जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करना मुश्किल है।

इंटकी गुण्डों द्वारा किए 17 सीटू कर्मियों के कत्ल की तीव्र भर्त्सना

[सीटू तथा प्लांटेशन वर्कर्स फैडरेशन आफ इण्डिया की ओर से सीटू सचिव विमल रणदिवे ने इंटकी दरिंदों द्वारा की गई जघन्य हत्याओं की तीव्र भर्त्सना करते हुए 17 जून को निम्नलिखित प्रेस वक्तव्य जारी किया]

सीटू तथा प्लांटेशन वर्कर्स फैडरेशन ने इन्टक के हत्यारे गिरोह द्वारा 17 सीटू कर्मियों की दर्दनाक हत्या पर कड़ा रोष प्रकट किया है। इस गिरोह ने अपने हमले में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी क्षेत्र के बनरहाट चाय बगान में सैकड़ों अन्य सीटू कर्मियों को घायल कर दिया। हमला बिलकुल अनुत्तेजित एवं पूर्व नियोजित था। क्योंकि जब सीटू की बैठक पर हमला किया गया उस समय अन्धेरा छाया हुआ था। हत्यारों ने बच निकलकर भागने का रास्ता भी बन्द कर दिया। बैठक पर हमले के अतिरिक्त उन्होंने क्षेत्र के कुछ गांवों पर आक्रमण किया। उन पर कई घंटों तक आग्नेयास्त्रों, बमों, तीरों तथा घातक हथियारों से हमले जारी रहे। यहाँ पुलिस कार्यवाही में बाधा डालने के सभी प्रबन्ध भी किए गये थे।

राज्य कांग्रेस (आई) के साये तले आनन्द करते इंटक के अदूरदर्शी स्थानीय नेता शायद यह नहीं जानते कि उनका यह कातिलाना तांडव स्वस्थ मजदूर आन्दोलन के वातावरण को बिगाड़ेगा जिससे कामकाजी वर्ग के आन्दोलन के लिए हानिकारक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सीटू आशा करता है कि इंटक का उच्च नेतृत्व इस मामले की तह तक छानबीन करने से पीछे नहीं हटेगा। वह न केवल इस जघन्य हमले का विरोध करेगा अपितु भविष्य में अपने कार्यकर्ताओं पर भी नियंत्रण रखेगा।

मजदूरों ने अपने गहरे रोष का प्रदर्शन स्थानीय तथा जिला स्तरों पर बन्द द्वारा किया। सीटू तथा प्लांटेशन वर्कर्स फैडरेशन मजदूरों से इस क्रूर जनसंहार के विरोध करने का आह्वान करता है।

सीटू तथा प्लांटेशन वर्कर्स फैडरेशन मांग करती है कि अपराधियों को कड़ी सजा तथा घायलों एवं मृतकों के परिवारों को पर्याप्त राहत दी जाए।

सीटू तथा प्लांटेशन वर्कर्स फैडरेशन ने घायलों के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति तथा शोक संतृप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है।

बैठक की कार्रवाई

कार्यसमिति का भुवनेश्वर सत्र महत्वपूर्ण रहा क्योंकि उसमें संगठनात्मक रिपोर्ट को पारित किया गया जो पिछले सात माह से संगठन के विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन थी। विचार-विमर्श का आरंभ 27-28 नवम्बर, 1992 को दिल्ली में हुई कार्यसमिति की बैठक में हुआ था।

सीटू के अध्यक्ष कॉ. ई. बालानन्दन ने यात्री निवास पर 4 जून को साढ़े दस बजे ध्वजारोहण करके तथा शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यक्रम का आरम्भ किया।

उद्घाटन सत्र

आरम्भ में स्वागत समिति के अध्यक्ष, सीटू की उड़ीसा राज्य समिति के अध्यक्ष तथा सांसद शिवाजी पटनायक ने अपने संक्षिप्त भाषण में प्रतिनिधियों का स्वागत किया। तत्पश्चात् का. ई. बालानन्दन ने उद्घाटन भाषण दिया। उद्घाटन भाषण में उन्होंने बंगलौर की जनरल काउंसिल बैठक के बाद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर घटी घटनाओं के बारे में संक्षेप में समझाया। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने विकसित देशों में जारी मंदी के बारे में बताया। उन्होंने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि इनमें से अनेक देशों में आसमान छूती बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष आरंभ हो गया है। लेकिन नेतृत्व की वैचारिक सीमाओं के कारण ये संघर्ष वांछित गति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अपने भाषण में का. बालानन्दन ने साम्राज्यवादी चालों, खासकर अमरीकी इरादों के बारे में सचेत किया जो अमरीका-यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा जापान के बीच केन्द्रित व्यापार प्रतिस्पर्धा के समाधान के उद्देश्य से तृतीय विश्व के देशों को पुनः उपनिवेश बनाना चाहता है।

ऐसी परिस्थिति में उन्होंने मजदूर आंदोलन से नयी आर्थिक नीतियों व सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष तेज करने की अपील की। उन्होंने श्रम संगठनों से अपील की कि वे राष्ट्रीय स्तर पर बनायी गयी एकता को आगे बढ़ाएं तथा 9 सितम्बर के भारत बन्द व आम हड़ताल को सफल बनाएं। (उद्घाटन भाषण का सार इस अंक में प्रकाशित हुआ है।)

उद्घाटन सत्र का अभिनन्दन उड़ीसा इंटक के अध्यक्ष रामचन्द्र खुंटिया, उड़ीसा के श्रम मंत्री श्री मंगन किसान ने किया।

इसके बाद दो प्रस्ताव रखे गये। 9 सितम्बर के भारत बन्द पर प्रस्ताव का. चित्तब्रत मजूमदार ने रखा व का. एम.एम. लारेंस ने उसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रतिनिधियों ने भारत बन्द तथा 19 अगस्त के जेल भरो आंदोलन को जबर्दस्त सफलता प्रदान करने के लिए व्यापक तैयारियाँ करने की आवश्यकता पर बल दिया।

14 जुलाई को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की अखिल भारतीय हड़ताल पर प्रस्ताव सीटू के सचिव का. पी.के. गांगुली ने रखा तथा का. चन्द्रशेखर ने उसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव के समर्थन में निम्नलिखित वक्ता बोले: एन. प्रसाद राव व का. एस. सूर्यनारायण राव (उपाध्यक्ष), विमल रणदिवे (सचिव), बंगाल से काली घोष व तमिलनाडु से एन. परमेश्वरन्।

संगठनात्मक रिपोर्ट पर विचार-विमर्श

उद्घाटन सत्र के तुरन्त बाद का. एम.के.पंधे (महासचिव) ने बंगलौर जनरल काउंसिल बैठक के बाद तैयार की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने विभिन्न राज्य समितियों द्वारा मसौदे पर भेजे गये सुझाव व संशोधन भी पेश किये। रिपोर्ट पेश किये जाने के बाद उस दिन के सत्र की समाप्ति हुई।

5 जून को सुबह रिपोर्ट पर विचार-विमर्श आरम्भ हुआ तथा देर रात तक 6 जून की सुबह तक चला। कुल मिलाकर विभिन्न राज्यों व औद्योगिक फेडरेशनों का प्रतिनिधित्व कर रहे 26 साथियों ने विचार-विमर्श में हिस्सा लिया। केन्द्र को मजबूत बनाने, हिन्दी भाषी क्षेत्रों तथा अन्य औद्योगिक राज्यों, जहाँ सीटू की स्थिति कमजोर है, वहाँ सीटू को सुदृढ़ करने के बारे में अनेक संशोधन रखे गये। वर्ग-एकता तथा संगठित आंदोलन विचार-विमर्श के केंद्र के रूप में उभरे। कैडर को प्रशिक्षित करने के लिए संस्थान विकसित करने के बारे में सदस्यों ने राय प्रकट की।

विचार-विमर्श का समापन

महासचिव, का. एम.के. पंधे ने विचार-विमर्श का समापन किया। उन्होंने अनेक संशोधनों को स्वीकार किया। अपने समापन भाषण में उन्होंने घोषणा की कि एक माह के भीतर संगठनात्मक रिपोर्ट जारी कर दी जायेगी। इसके बाद कार्यान्वयन

का प्रश्न आया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के संगठन के अतिरिक्त और कोई गारंटी नहीं है। आरंभ में ही उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि हमें ऐसी संगठनात्मक गारंटी तैयार नहीं करनी चाहिए कि सभी नेतृत्वकारी समितियाँ यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन समितियाँ रिपोर्ट का सही अर्थ में अनुपालन करती हैं। उन्होंने लगातार नये साथियों व कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए नेतृत्व को सुदृढ़ बनाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। समाज के पिछड़े वर्गों से आने वाले साथी व कामगार महिलाएं। अन्त में उन्होंने कहा कि संगठनात्मक पुनर्ध्रुवीकरण की प्रमुख शक्ति समाज में बदलाव की मूल अवधारणा है। यदि वैचारिक अवधारणा कमजोर होती है तो संगठन भी कमजोर हो जाता है।

अन्त में कार्यसमिति द्वारा स्वीकृत संशोधनों सहित रिपोर्ट पास हुई।

तत्पश्चात का. रंजीत बसु ने कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट रखी जो पास हो गयी।

मिलबंदी तथा मंदी पर विचार-विमर्श

का. एम.के. पंधे ने औद्योगिक बीमारी तथा 56 केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के बन्द होने के बारे में विचार-विमर्श आरंभ किया। कुल मिलाकर का. पंधे द्वारा रखी गयी रिपोर्ट पर 10 सदस्यों ने विचार व्यक्त किये।

उपाध्यक्ष, का. उमानाथ ने विचार-विमर्श में हस्तक्षेप किया। बीमार उद्योगों का जल्द से जल्द अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाने का फैसला किया गया ताकि विरोध का कार्यक्रम निर्धारित किया जा सके। कार्यसमिति ने बी.आई.एफ.आर को सौंपे गये मामलों में षड्यन्त्रकारी रुख पर चिन्ता प्रकट की। सरकारी प्रतिनिधि निजीकरण की स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद जहाँ पुनर्वास की संयुक्त योजनाएं प्रस्तुत की गयीं हैं वहाँ भी उन्हें मंजूरी नहीं दी गयी है।

तत्पश्चात, कार्यसमिति ने सितम्बर की हड़ताल की तैयारियों का जायजा लिया व उन्हें तेज करने का निर्णय किया। जहां तक सीटू के आठवें सम्मेलन का प्रश्न है उसे 1994 के प्रथम पखवाड़े में आयोजित किया जायेगा। स्थान व तिथि निश्चित करने का अधिकार सचिव मंडल को प्रदान किया गया।

कार्यसमिति ने क्रेडेंसियल कमेटी की रिपोर्ट को पारित किया। चार प्रस्ताव भी पास किये गये। तत्पश्चात वर्ष की आडिट रिपोर्ट को स्वीकार किया। धन्यवाद प्रस्ताव के साथ अधिवेशन समाप्त हुआ।

भारत में कोसाटु प्रतिनिधिमंडल अध्ययन के दौरे पर

कांग्रेस ऑफ साउथ अफ्रीकन ट्रेड यूनियन्स (कोसाटु) का एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मई, '93 के दूसरे पखवाड़े में भारत पधारा। दौरे का उद्देश्य प्रौढ़-शिक्षा के भारतीय सहकर्मियों से अनुभव बाँटना था। दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों की प्रौढ़-शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है जहाँ जनसंख्या का 60% हिस्सा पढ़ या लिख नहीं सकता। जातिवादी सरकार के रंगभेद वाले कानूनों ने इन लोगों को बुनियादी शिक्षा से वंचित रखा। इसीलिए कोसाटु ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर अफ्रीका में निरक्षरता को दूर करने के लिए एक एक विशाल कार्यक्रम चलाया है।

प्रतिनिधिमंडल 19 मई की सुबह को बम्बई से दिल्ली आया। अपने छह दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने सीटू, इंटक, एच.एम.एस तथा एटक नेताओं के साथ गंभीर बातचीत की। उन्होंने कई प्रौढ़-शिक्षा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तथा भारत ज्ञान-विज्ञान समिति के मुख्यालय, दिल्ली साक्षरता समिति तथा इन्हीं द्वारा अम्बेडकर नगर नई दिल्ली में चलाए जा रहे साक्षरता केंद्र का दौरा किया।

21 मई को प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय श्रम मंत्री पी.ए. संगमा के कार्यालय पर उनसे भेंट की। 24-5-93 की सुबह को सीटू की दिल्ली राज्य समिति ने गाजियाबाद की दो फैक्टरियों के दौरे का कार्यक्रम बनाया। शाम को सीटू के केन्द्रीय कार्यालय में रंगभेद के खिलाफ 'भारतीय ट्रेड यूनियन कमेटी' ने उनके सम्मान में सार्वजनिक सत्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। दूसरे लोगों के बीच ए.एन.सी. के प्रतिनिधि एम. एफिले ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लोगों द्वारा शासन के विरुद्ध चलाए जा रहे साहसी संघर्ष तथा जातिवाद रहित लोकतांत्रिक समाज स्थापना का संक्षिप्त ब्यौरा दिया। सीटू के महासचिव एम.के. पंधे, एटक के सक्रिय महासचिव बी.डी.जोशी, एच.एम.एस सचिव विरेश्वर त्यागी, इंटक उपाध्यक्ष रचन्द्र खुंटिया ने भारतीय मजदूर लोगों की दक्षिण अफ्रीका के संघर्षशील लोगों के साथ अपनी एकता व्यक्त की।

उत्सव में समिति द्वारा भारत के ए.एन.सी. डिप्लोमैटिक मिशन को हाई स्पीड फोटो कापी मशीन भेंट की गई। प्रतिनिधिमंडल के प्रत्येक सदस्य को, रुचिपूर्ण ढंग से बनाया हुआ पीतल का मोर भेंट किया गया। बाद में डब्ल्यू.एफ.टी.यू. एशिया पैसिफिक रीजनल ऑफिस सचिव ओ.के. गांगुली ने मेहमान प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में रात्रि भोज दिया। 25 मई '93 को प्रतिनिधिमंडल कोचीन रवाना हो गया।

9 सितम्बर को भारत बन्द

4.5 जून, 1993 को भुवनेश्वर में हुई सीटू की कार्यसमिति की बैठक में औद्योगिक हड़ताल सहित भारत बन्द के फैसले का पूर्ण समर्थन किया गया जो 15 अप्रैल, 1993 को नई दिल्ली में हुए जन संगठनों के सम्मेलन में किया गया था। बन्द का आह्वान नरसिम्हा राव सरकार की राष्ट्र-विरोधी आर्थिक नीतियों तथा सांप्रदायिकता के खिलाफ जनता व मजदूर वर्ग का दृढ़ विरोध प्रकट करने के लिए किया गया।

बैठक में नोट किया गया 'सरकार की आर्थिक नितियों व सांप्रदायिकता के खिलाफ जन संगठनों के मंच' का निर्माण समय की मांग है तथा इसे देश के संगठित लोकतांत्रिक आन्दोलन की एक उपलब्धि मानना चाहिये। कार्यसमिति मजदूर वर्ग से अपील करती है कि वह इस ऐतिहासिक एकता को आगे बढ़ायें तथा इसे और सुदृढ़ बनाने का हर संभव प्रयास करें।

कार्यसमिति ने धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक जनता, मजदूर वर्ग, किसानों, कृषि मजदूरों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, वैज्ञानिकों व कलाकारों के जन संगठनों से अपील की कि वे संघर्ष व प्रचार कार्यक्रमों में सक्रिय भागेदारी करें तथा इस बन्द को शानदार सफलता प्रदान करें। बन्द के प्रचार अभियान को समाज के सभी तबकों व गली-कूचों तक पहुंचना चाहिए तथा इसमें जनता की व्यापक भागेदारी सुनिश्चित् करनी चाहिये। इन नीतियों के के खिलाफ विरोध कार्यक्रमों की घोषणा करके श्रम संगठनों ने जो उदाहरण पेश किया है, उसी जिम्मेदारी को उन्हें आगे निभाना होगा।

कार्यसमिति ने सीटू की राज्य समितियों व जिला समितियों, यूनियनों व औद्योगिक फेडरेशनों से अपील की कि वे इस नये मंच की राज्य स्तरीय समितियाँ गठित करने, राज्य, जिला, ताल्लुकात व क्षेत्रीय स्तर पर सम्मेलन आयोजित करने तथा 19 अगस्त के गिरफ्तारी के कार्यक्रम सहित जनता को भारत बन्द के लिए लामबन्द करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन में जो कार्यक्रम तय किये गये थे उन पर अमल करें।

9 सितम्बर के भारत बन्द का महत्व इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि दो एक-दिवसीय सांकेतिक हड़तालों तथा लाखों मजदूरों द्वारा 25 नवम्बर को संसद के समक्ष किए गए जबर्दस्त प्रदर्शन के बावजूद भारत सरकार अपनी राष्ट्र-विरोधी नीतियों पर आगे बढ़ती जा रही है तथा इन नीतियों के राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को भी नजरअंदाज कर रही है। दूसरी ओर सांप्रदायिक शक्तियाँ भी अपने इरादों को पूरा करने के लिए अपनी विभाजनकारी गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं। ऐसी स्थिति में देश को आर्थिक व सामाजिक संकट से उबारने का जनता के सभी वर्गों के संगठित आन्दोलन के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। अतः भारत बन्द व उससे सम्बन्धित कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की शिथिलता संगठित आन्दोलन के लिए हानिकार होगी तथा उससे उपर्युक्त खतरों के विरुद्ध आन्दोलन को आघात पहुंचेगा।

अतः कार्यसमिति सीटू की सभी इकाइयों से अपील करती है कि वे दिल्ली घोषणा-पत्र को अमल में लाने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा देश भर में जनता में संघर्ष का मूड पैदा करने के लिए तुरन्त पहल करें ताकि भारत बन्द को ऐसी सफलता प्रदान की जा सके जो देश की अखंडता व संप्रभुता को विश्व बैंक-मुद्रा कोष व बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे साम्राज्यवादी एजेंटों की चालों से पैदा खतरे को दूर करने के लिए और बड़े कार्यक्रम का पथ-प्रशस्त कर सके।

आंगनवाड़ी महिलाएं भारत बन्द में हिस्सा लेंगी

19 जून को 14 अशोक रोड, नई दिल्ली में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स की बैठक हुई। का. विमल रणदिवे ने बैठक की अध्यक्षता की। इसकी शुरुआत शहीदों को श्रद्धांजलि के प्रस्ताव के साथ हुई। जलपायी गुड़ी जिले के बनराहट में रैड बैंक गार्डन में इंटक के हमले के शिकार हुए 13 बागान मजदूरों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया तथा इस हमले की तीव्र भर्त्सना की गई।

का. रणदिवे ने अपने अध्यक्षीय भाषण में संगठन की कमजोरियों के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि इन कमजोरियों को सुधारते हुए हमें संगठन को चुस्त करना होगा।

महासचिव का. बिनीलिमा राय ने एक रिपोर्ट रखी तथा विभिन्न राज्यों में चलाए जा रहे संघर्ष की उपलब्धियों पर वक्तव्य दिया। पांडिचेरी महिलाओं ने लम्बे संघर्ष के बाद 8 सौ रुपये बोनस प्राप्त किया। हमारी राज्य समिति तथा संयुक्त संघर्ष समिति के निरंतर संघर्ष के परिणामस्वरूप ही मानदेय में वृद्धि हुई। उन्होंने सदस्यों से अपील की कि वे बैठक में उपस्थित रहा करें तथा सदस्यता शुल्क को नियमित रूप से भेजते रहें। का. भबतोष राय ने भी इसे मजबूत संगठन बनाने की अपील की। बातचीत में बहुत से राज्यों ने हिस्सा लिया। भविष्य में निम्नलिखित मुख्य कार्यक्रम तय किये गये :

(1) 19 अगस्त के गिरफ्तारी देने का कार्यक्रम में तथा 9 सितम्बर के भारत बन्द में संपूर्ण हिस्सेदारी, तथा

(2) पूरे देश भर में 12 जुलाई को माग दिवस मनाया जाएगा।